रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED NO. D. (D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 23, 1978/पौष 2, 1900
No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER, 23 1978/PAUSA 2, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1978

का० आ० 3620.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के परामर्श से श्री सतीश चन्द्र के स्थान पर श्री जी०के० भट्टाचार्य, कलक्टर, दादरा और नागर हवेली को उनके कार्य-भार संभालने की तारीख से अगले आदेशों तक दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में एतद्वारा नामनिर्देशित करता है।

[सं० 154/दमह/78]

टी० नागरत्नम, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 22nd November, 1978

S.O. 3620.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Administration of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, hereby nominates Shri G. K. Bhattacharya, Collector Dadra and Nagar Haveli as the Chief Electoral Officer for the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Shri Satish Chandra.

[No. 154/DNH/78]

T. NAGARATHNAM, Secy.

New Delhi, the 29th November, 1978

S.O. 3621.—In pursuance of section III of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby publishes the report of the High Court at Calcutta, dated the 10th November, 1978, in Election Petition No. of 1977.

ELECTION PETITION CASE NO. 2 of 1977

HIGH COURT AT CALCUTTA

Election Petition Jurisdiction

In the matter of Lutfal Haque (Hazi)—Petitioner,

Versus

Sasanka Sekher Sanyal & Ors.—Respondents

For Petitioner—8-Jangipur parilamentary constituency

Sl. No.	Date	Notes and orders.
1	2	3
	10-11-78	Mr. Arunendu Sundar Ray files affidavit of service affirmed by Nirmalendu Nag on 8-11-78

1	2	3
		and states that publication has been duly made in the Calcutta Gazette dated 14-9-78. Hands over a copy of the Calcutta Gazette. Mr. J. N. Halder appears submits. The Court: Leave granted to withdraw the Election Petition in terms of prayer (a) of the petition. Order in terms of prayer (b) of the petition also. Registrar O. S. is to take necessary steps for publication of this order under the Rule. Let the copy of the Calcutta Gazette be kept with the records. Sabyasachi Mukharji

[No. 82/WB/2/77]

आदेश

का०आ० 3622—निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो चुका है कि जून, 1977 में हुए विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए पंजाब के 74 शुत्रराना (अ०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गुरदयाल सिंह, ग्राम शादीपुर मोमियन, डा० साधारण पुर, तहसील सामाना, जिला पटियाला (पंजाब) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग को यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गुरदयाल सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

आदेश से,

[सं० पंजाब-वि०स० /74/77]

बी० नागसुब्रमण्यन, सचिव

ORDER

S.O. 3622.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gurdial Singh, Village Shadipur Momian, P. O. Sadhranpur Tehsil Samana, District Patiala (Punjab), who was a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly from 74-Shutrana (SC) held in June, 1977 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after the due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Gurdial Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

By order,

[No. PB-LA/74/77]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 1978

आय-कर

का०आ० 3623.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर नियम, 1962 के नियम 6(ii) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा अनुसन्धान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक अनुसंधान सेवा" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात :—

(i) यह कि संस्था चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का हिसाब पृथक से रखेगी ।

(ii) उक्त संस्था प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की एक वार्षिक विवरणी परिषद को प्रति वर्ष अधिक से अधिक 31 मई तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं ।

संस्था

भारतीय चिकिरण संरक्षा संगठन, मुम्बई

यह अधिसूचना 4-9-1978 से 3-9-1980 तक की 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त होगी।

[सं० 2539(फा०सं० 203/139/78 आई टी ए II)]

जे० पी० शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Reveune)

New Delhi, the 9th October, 1978

INCOME TAX

S.O. 3623.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (I) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with rule 6 (ii) of the Income Tax Rules 1962 under the category of "Scientific Research Association" in the field of Medical Research, subject to the following conditions :—

(1) That the Institution will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of medical research.

(2) That the institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the Council for each financial year by 31st May each year at the latest in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.

INSTITUTION

INDIAN ASSOCIATION FOR REDIATION PROTECTION, BOMBAY

This notification is effective for a period of 2 years from 4-9-1978 to 3-9-1980

[No. 2539 (F. No. 203/139/78-ITA. II)]

J. P. SHARMA, Director

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1978

आय-कर

का०आ० 3624.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री सुब्रमण्य स्वामी आदि

कार्तिकेय लक्ष्मारचना कमिटि, सिकन्दराबाद को निर्धारण वर्ष 1977-78 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 2572/फा०सं० 197/147/78-आ०क०(ए१)]

एम० शास्त्री, अवर सचिव

New Delhi, the 7th November, 1978

INCOME TAX

S.O. 3624.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of the sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies Sri Subramanya Swami Adi Krithikai Laksharchana Committee, Secunderabad for the purpose of the said section for and from the assessment year 1977-78.

[No. 2572/F. No. 197/147/78-IT(AI)]

M. SHASTRI, Under Secy.

वित्तीय कार्य विभाग

बैंकिंग प्रभाग

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1978

का० आ० 3625.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (i) और (ii) तथा धारा 10-ख की उपधारा (2) और (4) के उपबन्ध, इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक आंध्र बैंक लिमिटेड, हैदराबाद पर, उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि उक्त उपबन्ध, इसके अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को बोर्ड ऑफ आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन, हैदराबाद के निदेशक बनने पर प्रतिबन्ध लगाते हैं, क्योंकि वह कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन एक पंजीकृत कम्पनी है।

[सं० 15(24)-बी० ओ० III/78]

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(Banking Division)

New Delhi, the 22nd November, 1978

S.O. 3625.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India hereby declares that the provisions of sub-clauses (i) and (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 and sub-section (2) and (4) of section 10B of the said Act shall not apply to the Andhra Bank Ltd., Hyderabad, for a period of one year from the date of this notification in so far as the said provisions prohibit its Chairman and Chief Executive Officer from being a director on the Board of Andhra Pradesh Industrial Development Corporation, Hyderabad, being a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

[No. 15(24)-B.O.III/78]

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1978

का० आ० 3626.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10-ख की उपधारा (1) और (2) के उपबन्ध बैंक ऑफ कोचीन लिमिटेड पर 5 जून, 1979 तक अथवा उस बैंक के अगले पूर्ण कालिक अध्यक्ष की नियुक्ति तक, दोनों में से जो भी पहले हो उस तक, लागू नहीं होंगे।

[सं० 15(28)-बी०ओ० III/78]

मे० मा० उसगांवकर, अवर सचिव

New Delhi, the 5th December, 1978

S.O. 3626.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-sections (1) and (2) of section 10B of the said Act, shall not apply to Bank of Cochin Ltd., till the 5th June, 1979 or till the appointment of the next whole-time Chairman of that Bank, whichever is earlier.

[No. 15(28)-B.O. III/78]

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1978

का०आ० 3627.—औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की धारा 21 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक मंडल की सिफारिश पर एतद्द्वारा उन बांडों पर दिये जाने वाले ब्याज की दर 6 1/4 प्रतिशत (सवा छः प्रतिशत) वार्षिक निर्धारित करती है जो उक्त निगम द्वारा 14 दिसम्बर, 1978 को जारी किए जायेंगे तथा 14 दिसम्बर, 1988 परिपक्व होंगे।

[एफ० संख्या 2(95) आई०एफ० 1/78]

बी०सी० पटनायक, निदेशक

New Delhi, the 6th December, 1978

S.O. 3627.—In pursuance of sub-section (2) of section 21 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948), the Central Government on the recommendation of the Board of Directors of the Industrial Finance Corporation of India, hereby fixes 61/4 per cent (six and a quarter per cent) per annum as the rate of interest payable on the bonds to be issued by the said Corporation on the 14th December, 1978 and maturing on the 14th December, 1988.

[No. F. 2(95)/IF1/78]

B. C. PATNAIK, Director

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1978

का०आ० 3628.—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन सुरेन्द्रनगर काटन आयल एण्ड आयलसीड्स एसोसिएशन लिमिटेड, सुरेन्द्रनगर द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किये गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एसोसिएशन को कपास की अग्रिम संविदाओं के बारे में 11 दिसम्बर, 1978 से 10 दिसम्बर, 1979 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी शामिल हैं) की एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता है।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एसोसिएशन ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय समय पर दिये जायें।

[फा.सं. 12(23)-आई०डी०/78]

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Civil Supplies and Cooperation)

New Delhi, the 27th November, 1978

S.O. 3628.—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Surendranagar Cotton Oil and Oilseeds Association Limited, Surendranagar, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a further period of one year from the 11th December, 1978 to the 10th December, 1979 (both days inclusive), in respect of forward contracts in cotton.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions, as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[File No. 12(23)-IT/78]

का०आ० 3629.—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन इंडियन एक्सचेंज लि०, अमृतसर द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए दिए गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को बिनौले की अग्रिम संविदाओं के बारे में 11 नवम्बर, 1978 से 10 नवम्बर, 1979 (जिसमें दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्द्वारा, प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्यधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा, जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जायें।

[मिसिल सं० 12(22)-आई०टी०/78]

के०एस० मैथ्यू, उप सचिव

S.O. 3629.—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Indian Exchange Limited, Amritsar and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of one year from the 11th November, 1978 to the 10th November, 1979 (both days inclusive) in respect of forward contracts in cottonseed.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions, as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[File No. 12(22)-IT/78]

K. S. MATHEW, Dy. Secy.

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1978

(रबड़ नियंत्रण)

का०आ० 3630.—रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने श्री एस०जी० सुन्दरम आई० ए० एस० को 26 अगस्त, 1978 से और आदेश होने तक, रबड़ बोर्ड, कोट्टयाम-1 का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

[फाइल सं० 21(2)/78-प्लान्ट(बी)]

(Department of Commerce)

New Delhi the 2nd December, 1978

RUBBER CONTROL

S.O. 3630.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 4 of the Rubber Act, 1947 (24 of 1947), the Central Government has appointed Shri S. G. Sundaram, I.A.S. as Chairman, Rubber Board, Kottayam-1, with effect from the 26th August, 1978, until further orders.

[File No. 21(2)/78-Plant(B)]

(इलायची नियंत्रण)

का०आ० 3631.—केन्द्रीय सरकार ने, इलायची अधिनियम, 1965 (1965 का 42) की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एस०जी० सुन्दरम आई०ए०एस० को 26 अगस्त, 1978 से तब तक के लिए, जब तक कि कोई नियमित पदधारी नियुक्त नहीं किया जाता, इलायची बोर्ड, एर्नाकुलम, कोचीन का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

[फाइल सं० 21/(2)/78-प्लान्ट (बी)]

एस० महादेव अय्यर, उप निदेशक

(CARDAMOM CONTROL)

S.O. 3631.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 4 of the Cardamom Act 1965 (42 of 1965), the Central Government has appointed Shri S. G. Sundaram, I.A.S. as Chairman of Cardamom Board, Ernakulam, Cochin, with effect from the 26th August, 1978 until a regular incumbent is appointed to that post.

[F. No. 21(2)/78-PLANT(B)]

S. MAHADEVA IYER, Dy. Director

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 1978-12-05

का०आ० 3632.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसरण में भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी एम/एल-4238 जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं 1978-11-15 से रद्द कर दिया गया है क्योंकि फर्म अब लाइसेंस को चालू रखने की इच्छुक नहीं है।

अनुसूची

क्रम सं०	लाइसेंस सं०	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्संबंधी भारतीय मानक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सी एम/एल-4238 1975-02-21	मैसर्स ट्यूब प्रोडक्टस आफ इंडिया, अयदी मद्रास-600054	साईमिकल और अन्य कार्यों के लिए इस्पात की नलियां ग्रेड : "ई आर डब्ल्यू" और "सी ई डब्ल्यू" मार्का : टी आर-वल	: 2039—1964 साईमिकल और अन्य कार्यों के लिए इस्पात नलियों की विशिष्टि

[सं० सी एम डी/55 : 4238]

ए० पी० बनर्जी, उपमहानिदेशक

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, 1978-12-05

S. O. 3632.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks), Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L-4238 particulars of which are given below has been cancelled with effect from 1978-09-15 as the firm is not interested in operating the licence.

SCHEDULE

Sl No.	Licence No. and Date	Name & Address of the Licensee	Article/Process Covered by the Licensees Cancelled	Relevant Indian Standards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	CM/L—4238 1975-02-21	M/s Tube Products of India, Avadi, Madras-600054	Steel tubes for bicycle and allied purposes grade : 'ERW' and 'CEW' Brand : TRU-WEL	IS : 2039—1964 Specification for steel tubes for bicycle and allied purposes.

[CMD/55 : 4238]

A. P. Banerji, Dy. Director General

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1978

का०आ० 3633.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकारी को सरकार का राजपत्रित अधिकारी होने के नाते, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है और आगे यह निदेश करती है कि उक्त अधिकारी उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत अपनी अधिकारिता के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन संपदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
श्री कुल भूषण लाल मलिक, सहायक प्रबन्धक, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, लिमिटेड, नई दिल्ली-110020	निगम के स्वामित्व उसके द्वारा अर्जित या किराए पर ली गई औद्योगिक सम्पदा, नैनी, डाक घर उद्योग नगर, इलाहाबाद, यू०पी० की भूमि और भवन।

[फा० सं० एस०एस०आई० (1)-14(47)/78]

डी० एस० बावा, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 24th October, 1978

S.O. 3633—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being an officer equivalent to the rank of Gazetted Officer of the Government to be Estate Officer for the purpose of the said Act and further direct that said officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officers by or under the said Act within the limits of his jurisdiction in respect of public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the Officer	Categories of the Public Premises and Local Limits of Jurisdiction
1	2
Shri Kul Bhushan Lal Malik, Assistant Manager, The National Small Industries Corporation Limited, New Delhi-110020.	Land and buildings of the Industrial Estate, Naini, Post Office Udyog Nagar, Allahabad, U.P. owned, acquired or hired by the Corporation.

[File No. SSI(I)-14(47)/78]

D. S. BAWA, Under Secy.

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1978

का०आ० 3634.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पोर्ट से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईप लाइन इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, सलाया-मथुरा पाईप लाइन प्रोजेक्ट, बी-18 शिवमार्ग, बनीपाक, जयपुर-6 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा। और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी अधिवक्ता व्यवसायी की मार्फत।

'अनुसूची'

तहसील : खारची जिला : पाली राज्य : राजस्थान

ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल		
		हैक्टर	एयर	वर्गमीटर
देवली (अऊवा)	1591	0	01	84
गुढ़ाकिसर सिंह	175	0	15	18
	51	0	01	84
गधाना	233	0	00	31
	284	0	00	31
	189	0	00	69
बोरनड़ी	145	0	00	13

[सं० 12020/5/78-प्रो०]

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZER

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 30th November, 1978

S.O. 3634.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh pipelines should be laid by the Indian Ooil Corpotion Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali Mathura Pipeline Project, B-18, Shiv Marg, Bani Park, Jaipur-6.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Tehsil : Kharchi District : Pali State : Rajasthan

Village	Khasra No.	Area		
		Sq. H.	A.	M.
Deoli (Auwa)	1591	0	01	84
Gurha Kesarsingh	175	0	15	18
	51	0	01	84
Gadhana	233	0	00	31
	284	0	00	31
	189	0	00	69
Bornari	145	0	0	13

[No. 12020/5/78-Prod.]

का०आ० 3635.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पोर्ट से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, सलाया-मथुरा पाईप लाइन प्रोजेक्ट, बी-18, शिव मार्ग बिना पार्क, जयपुर-6 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा। और

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

तहसील : देसुरी	जिला : पाली		राज्य : राजस्थान	
ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल		
		हैक्टर	एयर	वर्गमीटर
बड़ोद	72/6	0	02	43

[सं० 12020/6/78-प्रो०]

S.O. 3635.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali-Mathura Pipeline Project, B-18, Shiv Marg, Bani Park, Jaipur-6;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Tehsil : Desuri	District : Pali	State : Rajasthan		
Village	Khasra No.	Area		
		H.	A.	Sq. M.
Barod	72/6	0	02	43

[No. 12020/6/78-Prod.]

का०आ० 3636.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पोट से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिऐ,

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है,

यतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, सलाया-मथुरा पाईप लाइन प्रोजेक्ट बी-18 शिवमार्ग, बनी पार्क, जयपुर-6 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

तहसील : रायपुर	जिला : पाली		राज्य : राजस्थान	
ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल		
		हैक्टर	एयर	वर्गमीटर
रायपुर	2308/1	0	07	29
दीपावास	332	0	08	10
मैगवड़ा	83	0	05	12
माकड़वाली	80	0	00	81
फलाखड़ा	42/94	0	12	44
	39/93	0	08	10
सवंड़ा	658	0	00	14
	685	0	00	81
सबलपुरा II	218	0	00	60
	373	0	00	18
सराधना	181	0	03	10

[सं० 12020/6/78 प्रो०]

S.O. 3636.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali-Mathura Pipeline Project, B-18, Shiv Marg, Bani Park, Jaipur-6;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Tehsil : Raipur	District : Pali	State : Rajasthan		
Village	Khasra No.	Area		
		H.	A.	Sq. M.
Raipur	2308/1	0	07	29
Deepawas	332	0	08	10
Megdara	73	0	05	12
Makarwali	80	0	00	81
Fata Khera	42/94	0	12	44
	33/93	0	08	10
Sendra	658	0	00	14
	685	0	00	81
Sabalpura II	218	0	00	60
	373	0	00	18
Saradhna	181	0	03	10

[No. 12020/8/78-Prod.]

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1978

का० आ० 3637.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० एस पी०ए० से एन के-54 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

एस०पी०ए० से एन०के०-54 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाणा, अहमदाबाद तालुका : कड़ी, बिरमगम

गांव	सर्वेक्षण नं०	हैक्टेयर	एरीआई	सेंटीआर
चालासण	82	0	03	50
बालसासण	255	0	09	75
	254	0	01	80
	257	0	21	73

[सं० 12016/14/78-प्रो०]

New Delhi, the 6th December, 1978

S.O. 3637.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SPA to NK-54 in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of lying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals, pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SPA to NK-54

State : Gujarat Dist : Mehsana/Ahmedabad Taluka : Kadi/ Viramgam

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Chalasan	82	0	03	50
Balasasan	255	0	09	75
	254	0	01	80
	257	0	21	73

[No. 12016/14/78-Prod.]

का० आ० 3638.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० एस०डी०जी० से एस० डी०एफ० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

कूप नं० एस०डी०जी० से एस०डी०एफ०

राज्य : गुजरात   जिला : मेहसाना   तालुका : मेहसाना

गांव	सर्वेक्षण नं०	हेक्टेयर	एरीअई	सेन्टीअर
हेबुवा	50	0	07	50
	कार्ट ट्रैक	0	01	00
	72	0	05	40
	71	0	03	75
	73	0	07	00
	74	0	08	75
	91	0	06	50
	कार्ट ट्रैक	0	00	60
	86	0	06	67
	88	0	01	20
	290	0	07	75
	98	0	01	00

[सं० 12016/15/78-प्रो०]

S.O. 3638.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest for the transport of petroleum from SDG to SDF in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of lying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsetion (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerâls, Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas ommission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person malsing such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

ROV from SDG to SDF

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hect.	Are	Centiare
Hebuva	50	0	07	50
	Cart-track	0	01	00
	72	0	05	40
	71	0	03	75
	73	0	07	00
	74	0	08	75
	91	0	06	50
	Cart-track	0	00	60
	86	0	06	67
	88	0	01	20
	290	0	07	75
	98	0	01	00

[No. 12016/15/78—Prod.]

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1978

का०आ० 3639.—पेट्रोलियम मंत्रालय, नई दिल्ली दिनांक 16-12-1974, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम, 1962, जिला अहमदाबाद।

पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उपधारा (1) और धारा 6 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गुजरात राज्य के जिला—अहमदाबाद में तालुका—वीरमगाम, गांव—बालसासन में कूप संख्या 36 से सी०टी०एफ० से एन०के०-53 तक भूमि के उपयोग का अधिकार, पाइप-लाइन बिछाने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय, नई दिल्ली की क्रमश: अधिसूचना संख्या 12016/12/74-एल० एण्ड एल० दिनांक 16-12-1974 तथा संख्या 12016/12/74-एल० एण्ड एल० दिनांक 30-6-1975 के साथ संलग्न अनुसूची के स्थान पर अब से नीचे दी गई अनुसूची को पढ़ें।

पढ़ें				के लिए			
	क्षेत्रफल				क्षेत्रफल		
सर्वेक्षण संख्या	हैक्टेयर	एआरई	सेंटेयर	सर्वेक्षण संख्या	हेक्टेयर	एआरई	सेंटेयर
250/1	0	03	12	250	0	03	12

[संख्या 12016/12/74-एल० एण्ड एल०]

एस० एम० वाई० नदीम, अवर सचिव

ERRATUM

New Delhi, the 6th December 1978

S.O. 3639.—Ministry of Petroleum, New Delhi, dated 16-12-1974, Petroleum pipe lines (Acquisition of Right of User in land), Act, 1962, District—Ahmedabad.

In schedule appended to the Government Notification Ministry of Petroleum, New Delhi No. 12016/12/74-L&L dated 16-12-1974, issued under section 3(1) and Notification No. 12016/12/74-L&L dated 30-6-1975 issued under section 6(1) of Petroleum Pipelines Act, 1962, for the acquisition of right of user for laying pipeline from Well No. 36 to CTF to 53 in Gujarat State, Dist.-Ahmedabad, Taluka-Viramgam, Village-Balsasan.

READ				FOR			
	AREA				AREA		
Survey No.	Hectare	Are	Centiare	Survey No.	Hectare	Are	Centiar
250/1	0	03.	12	250	0	03	12

[12016/12/74-L&L]

S. M. Y. NADEEM, Under Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1978

का०आ० 3640.—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, नीचे की सारणी के

स्तम्भ (1) के वर्णित अधिकारी को, जो भारतीय खाद्य निगम, एक निगमित प्राधिकरण का एक अधिकारी है और जो भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त निगम के या उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए या उसके द्वारा या उसके निमित्त अधिग्रहित परिसरों की बाबत उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
उपमण्डलीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, मुम्बई।	मुम्बई में भारतीय खाद्य निगम के या उसके पट्टे पर लिए गए या उसके द्वारा या उसके निमित्त अधिगृहीत परिसर।

[फा०नं० 27-2/77-ख०पी० II]

के०सी०एस० आचार्य, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Food)

New Delhi, the 26th July, 1978

S.O.3640.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being an officer of the Food Corporation of India, a corporate authority, and being an officer equivalent to the rank of a gazetted officer of Government of India, to be an estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on estate officer by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction, specified in column (2) of the said Table, in respect of the premises belonging to, or taken on lease or requisitioned by or on behalf of, the said Corporation.

TABLE

Designation of officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Deputy Zonal Manager, Food Corporation of India, Bombay.	Premises belonging to, or taken on lease, or requisitioned by or on behalf of the Food Corporation of India in Bombay.

[F. No. 27-2/77—FC II]

K. C. S. ACHARYA, Joint Secy.

(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1978

का०आ० 3641.—केन्द्रीय सरकार, सामान्य श्रेणीकरण और सूचना नियम 1937 के नियम 4 के खण्ड (क) और (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय पर सभी पूर्व आदेशों को अधिक्रांत करते हुए "15 दिसम्बर, 1978 से निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दरों पर उसके स्तम्भ (1) और (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों के बारे में एगमार्क लेबल प्रभार नियत करती है।

सारणी

पण्य वस्तु	वर्ग/प्रजाति/प्रकार/श्रेणी इत्यादि	एगमार्क लेबल प्रभारों की दर	
(1)	(2)	(3)	
ऊन	(1) सफेद, आभा वाला सफेद, पीला और फीका पीला	100-200 कि०ग्राम नेट की प्रति गांठ	रु० 8.00
	(2) रंगीन	100-200 कि०ग्रा० नेट की प्रति गांठ	रु० 4.00
	(3) टैनरी	100-200 कि०ग्रा० नेट की प्रति गांठ	रु० 2.00
	(4) नमूने : सभी श्रेणियों और रंग के	1 कि०ग्राम से अधिक और ढाई कि०ग्रा तक प्रति पैकेट	रु० 0.70
शहद	1) सभी प्रकार और श्रेणियां	प्रति कि०ग्रा० या उसके भाग के लिए	रु० 0.70
	(2) नमूने : सभी प्रकार और श्रेणियां के	200 ग्रा० से अधिक किन्तु 2 कि०ग्राम से अनधिक का प्रति पैक	रु० 1.20
	व्यापार विवरण		
बकरे के बाल	(1) भारतीय बकरे के बाल	प्रति 10 कि०ग्राम या उसके किसी भाग के लिए	रु० 0.20
	(2) भारतीय प्रसाधित बकरे के बाल	प्रति 10 कि० ग्राम या उसके किसी भाग के लिए	रु० 0.70
	(3) भारतीय टैनरी बकरे के बाल	प्रति 10 कि०ग्राम या उसके किसी भाग के लिए	रु० 0.05
	(4) सभी व्यापार विवरण	1/2 कि०ग्राम० से अधिक और 2 कि०ग्राम० तक के प्रति पैक	रु० 0.20
इलायची	(1) सभी प्रजातियां और श्रेणियां	प्रति 10 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 2.00
मिर्च	(1) सभी प्रजातियां और श्रेणियां	प्रति 10 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 0.35
काली मिर्च	(1) पिन हैड को छोड़कर सभी प्रजातियां और श्रेणियां	प्रति 10 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 0.35
	(2) पिन हैड्स	प्रति 10 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 0.20

(1)	(2)	(3)	
सन	(1) सभी प्रजातियां और श्रेणियां	180 कि०ग्रा० की प्रति गांठ	रु० 1.70
अखरोट	(1) साबुत : सभी श्रेणियां	प्रति 10 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 0.20
	(2) गिरी : सभी श्रेणियां	प्रति 10 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 0.55
चन्दन तेल	(1) सभी श्रेणियां	प्रति 10 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 10.00
मोतिया (पामरोजा) तेल	(1) सभी प्रजातियां और श्रेणियां	प्रति 10 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लए	रु० 8.00
खस (वेटिवर) का तेल	(1) सभी प्रजातियां और श्रेणियां	प्रति 10 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 8.00
निम्बूघास का तेल	(1) सभी श्रेणियां	प्रति 10 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 3.00
यूकेलिप्टस तेल	(1) सभी श्रेणियां	प्रति 10 कि० ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 2.00
हल्दी (साबुत)	(1) गुटिका और गांठें	प्रति 10 कि०ग्रा० या उससे किसी भाग के लिए	रु० 0.20
हल्दी (पाउडर)	(1) सभी श्रेणियां	प्रति 10 यक०ग्राम० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 0.35
अदरक	(1) सभी प्रजातियां और श्रेणियां	प्रति 10 कि० ग्रा० या उसक किसी भाग क लिए	0.20
खाने का आलू (निर्यात के लिए)	(1) सभी प्रजातियां और श्रेणियां	प्रति 10 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 0.05
दाल (निर्यात के लिए)	(1) सभी प्रजातियां और श्रेणियां	प्रति 10 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 0.10
प्याज	(1) सभी जातियां और श्रेणियां	प्रति 25 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 0.10
लहसुन	(1) सभी प्रजातियां और श्रेणियां	प्रति 10 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 0.15
तेन्दू के पत्ते	(1) सभी श्रेणियां	प्रति 10 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 0.20
तम्बाकू	(क) वर्ग-1 प्रजातियां		
	(1) फ्लयू क्योर्ड वर्जीनिया पट्टी या पत्ती : श्रेणियां 1, 2, 3, 4, ए एफ, ए एस, ए टी, एफ एल जी, एल जी, एल बी वाई, उनकी मिश्रित श्रेणियां और एक्स	प्रति 100 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 3.00
	(ख) वर्ग 2 प्रजातियां :		
	(1) फ्ल्यू क्योर्ड वर्जीनिया (पट्टी, पत्ती या टुकड़े) श्रेणियां—एल एम जी, एम जी, एल जी वाई 2, बी और उनकी मिश्रित श्रेणियां और चमकीले तथा अर्ध चमकीले टुकड़े	प्रति 100 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 1.50
	(2) सनक्योर्ड वर्जीनिया पट्टी या पत्ती श्रेणियां बी बी टी, बी बी और बी बी आर	प्रति 100 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 1.50
	(3) सनक्योर्ड व्हाइट बर्ले पट्टी या पत्ती श्रेणियां : डब्लू बी एल, डब्ल्यू बी आर और डब्ल्यू बी डी	प्रति 100 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 1.50
	(4) सनक्योर्ड नाटू कन्ट्री : श्रेणियां सी बी टी; सी बी आर, सी डी के, सी एच बी आर, और सी एच डी	प्रति 100 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 1.50
	(5) सनक्योर्ड लाल अपोक्रिया : सभी श्रेणियां	प्रति 100 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 1.50
	(6) सनक्योर्ड लाल चपोडिया : सभी श्रेणियां	प्रति 100 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लए	रु० 1.50
	(7) सनक्योर्ड जुट्टी : सभी श्रेणियां	प्रति 100 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 1.50
	(8) सनक्योर्ड नाटू बीड़ी तम्बाकू फ्लेक्स :	(1) 50 कि०से कम का प्रति पैकेज	रु० 0.75
	प्रसंस्कृत अर्ध प्रसंस्कृत	(2) 50 से 100 कि०ग्रा० तक का प्रति पैकेज	रु० 1.50
	(9) सनक्योर्ड मोतीहारी : सभी श्रेणियां	प्रति 100 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 1.50
	(10) सनक्योर्ड जत्ती : सभी श्रेणियां	प्रति 100 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 1.50
	(11) सनक्योर्ड कलकतिया : सभी श्रेणियां	प्रति 100 कि०ग्राम या उसके किसी भाग के लिए	रु० 1.50
	(ग) वर्ग-3 प्रजातियां		

(1)	(2)	(3)	
	(1) फ्लयूक्योर्ड वर्जीनिया (पट्टी, पत्ती, चूरा या डंठल) श्रेणियां : डी जी; डी बी, डी डी बी, डी बी एल, काले, टुकड़े, चमकीली पी एल, गहरी पी एल, एफ एस, एफ एस 2 और डंठल	प्रति 100 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 0.80
	(2) सनक्योर्ड वर्जीनिया—पट्टी, पत्ती चूरा या डंठल श्रेणियां : बी जी, बी पी एल, बी-टुकड़े, बी एस और बी एस 2	प्रति 100 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 0.80
	(3) सनक्योर्ड व्हाइट बर्ले—पट्टी, पत्ती या टुकड़े श्रेणियां : डब्ल्यू बी पी एल, डब्ल्यू बी—टुकड़े, डब्ल्यू बी एस, और डब्ल्यू बी एस-2	प्रति 100 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 0.80
	(4) सनक्योर्ड नाटू कन्ट्री—पट्टी, पत्ती, चूरा या डंठल; श्रेणियां : सी जी, एस बी-2, एस बी एम, सी बी एल, डंठल, एन एस और एन एस-2	प्रति 100 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 0.80
	(5) सनक्योर्ड जती—सभी श्रेणियां	प्रति 100 कि०ग्राम या उसके किसी भाग के लिए	रु० 0.80
	(6) टाप लाफ—सभी श्रेणियां	प्रति 100 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 0.80
	(7) सनक्योर्ड जती बिशपाथ—सभी श्रेणियां	प्रति 100 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 0.80
	(घ) वर्ग—	(i) 1 कि०ग्रा० से कम का प्रति पैकेट	रु० 0.40
	नमूने	(ii) 1 से 5 कि०ग्रा० तक का प्रति पैकट	रु० 0.80
		(iii) 5 कि०ग्रा० से अधिक का प्रति पैकेट पैकिंग से संबंधित श्रेणी, वर्ग और प्रकार के लिए विनिर्दिष्ट दरों पर ।	
सौंफ	(1) सभी श्रेणियां 3		
	(क) जब श्रेणीकरण, विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा उसकी प्रयोगशाला के माध्यम से किया जाता है ।	प्रति 10 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 0.20
	(ख) जब श्रेणीकरण, राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला के माध्यम से किया जाता है ।	प्रति 10 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 0.10
मेथी	(1) सभी श्रेणियां :		
	(क) जब श्रेणीकरण, विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा उसकी प्रयोगशाला के माध्यम से किया जाता है ।	प्रति 10 कि०ग्रा या उसके किसी भाग के लिए	रु० 0.15
	(ख) जब श्रेणीकरण, किसी राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला के माध्यम से किया जाता है ।	प्रति 10 कि०ग्राम या उसके किसी भाग के लिए	रु० 0.10
सेलरी बीज	(1) सभी श्रेणियां		
	(क) जब श्रेणीकरण, विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा उसकी प्रयोगशाला के माध्यम से किया जाता है ।	प्रति 10 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 0.20
	(ख) जब श्रेणीकरण, किसी राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला के माध्यम से किया जाता है ।	प्रति 10 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 0.10
धनिया	(1) सभी श्रेणियां		
	(क) जब श्रेणीकरण, विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा उसकी प्रयोगशाला के माध्यम से किया जाता है ।	प्रति 10 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 0.15
	(ख) जब श्रेणीकरण, किसी राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला के माध्यम से किया जाता है ।	प्रति 10 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग तक	रु० 0.10
जीरा	(1) सभी श्रेणियां		
	(क) जब श्रेणीकरण, विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा उसकी प्रयोगाला के माध्यम से किया जाता है ।	प्रति 10 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग तक	रु० 0.35
	(ख) जब श्रेणीकरण, किसी राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला के माध्यम से किया जाता है ।	प्रति 10 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग तक	रु० 0.25
घी	(1) सभी श्रेणियां	प्रति 10 कि०ग्रा० या उसके किसी भी भाग तक	रु० 0.50
वनस्पति तेल	(1) सभी प्रजातियां और श्रेणियां	प्रति 10 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग तक	रु० 0.25

(1)	(2)	(3)	
खली	(1) सभी प्रजातियां और श्रेणियां	प्रति 10 कि०ग्राम या उसके किसी भाग के लिए	रु० 0.15
क्रीमरी मक्खन	(1) सभी प्रजातियां और श्रेणियां	प्रति 10 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 0.50
पिसे हुए मसाले (करी पाउडर सहित)	(1) इलायची पाउडर को छोड़कर सभी प्रजातियां और श्रेणियां	प्रति 10 कि०ग्रा० या उसके किसी भाग के लिए	रु० 0.35
करी पाउडर	(2) इलायची पाउडर	प्रति 10 कि०ग्राम या उसके किसी भाग के लिए	रु० 2.00
सभी फल	सभी प्रजातियां और श्रेणियां	100 फलों के प्रति कस या टोकरी के लिए	रु० 0.10
गन्ना, गुड़ (जैगरी)	सभी प्रजातियां और श्रेणियां	प्रति क्विंटल	रु० 0.10
खाने के आलू (बीज आलू सहित) जो निर्यात से भिन्न प्रयोजन के लिए हो	सभी प्रजातियां और श्रेणियां	प्रति क्विंटल	रु० 0.10
चूरा	सभी प्रजातियां और श्रेणियां	प्रति क्विंटल	रु० 0.10
अंडे	सभी प्रजातियां और श्रेणियां	प्रति 600 अंडों की टोकरी	रु० 0.10
चावल	सभी प्रजातियां और श्रेणियां	प्रति क्विंटल	रु० 0.10
गेहूं का आटा	सभी प्रजातियां और श्रेणियां	प्रति क्विंटल	रु० 0.00
दालें जो निर्यात से भिन्न प्रयोजन के लिए हों	सभी प्रजातियां और श्रेणियां	प्रति क्विंटल	रु० 0.10

[सं० एफ० 13-13/75-ए०-II]

प्रकाश चन्द्र, अवर सचिव

(Department of Rural Development)

New Delhi, the 4th December, 1978

S. O. 3641.—In exercise of the powers conferred by clauses (i) and (k) of rule 4 of the General Grading and Marking Rules, 1937 and in supersession of all previous orders on the subject, the Central Government hereby fixes, with effect from the 15th December, 1978 the Agmark label charges at the rates specified in column 3 of the table below in respect of the corresponding entries in column 1 and 2 thereof.

TABLE

Commodity	Group/variety/type/grade etc.	Rate of Agmark label charges	
(1)	(2)	(3)	
Wool	(i) White, tinged white, yellow & Pale yellow	Per bale of 100—200 Kg. net.	Rs. 8.00
	(ii) Coloured	Per bale of 100—200 Kg. net.	Rs. 4.00
	(iii) Tannery	Per bale of 100—200 Kg. net.	Rs. 2.00
	(iv) Samples, All grades and colour	Per packet of over 1/2Kg. and upto 2 1/2Kg.	Rs. 0.70
Bristles	(i) All types and grades	Per Kg. or part thereof.	Rs. 0.70
	(ii) Samples, All types and grades	Per pack of more than 200 gm. but not more than 2 kg.	Rs. 1.20
Goat Hair	Trade description:		
	(i) Indian Goat Hair (excluding Tannery)	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 0.20
	(ii) Indian Dressed Goat Hair	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 0.70
	(iii) Indian Tannery Goat Hair	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 0.05
	(iv) Samples, All trade descriptions	Per pack of over 1/2 Kg. and upto 2 Kg.	Rs. 0.20
Cardamom	(i) All varieties and grades	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 2.00
Chillies	(i) All varieties and grades	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 0.35
Black Pepper	(i) All varieties and grades except pin heads.	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 0.35
	(ii) Pin heads	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 0.20
Sann-Hemp	(i) All varieties and grades	Per bale of 180 Kg.	Rs. 1.70
Walnuts	(i) In-shell : All grades	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 0.20
	(ii) Shelled : All grades	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 0.55
Sandalwood Oil	(i) All grades	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 10.00
Palmarosa Oil	(i) All grades	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 8.00
Vetiver Oil	(i) All varieties and grades	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 8.00

(1)	(2)	(3)	
Lemongrass Oil	(i) All grades	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 3.00
Eucalyptus Oil	(i) All grades	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 2.00
Turmeric (whole)	(i) Bulbs and fingers	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 0.20
Turmeric Powder	(i) All grades	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 0.35
Ginger	(i) All varieties and grades	Per 10 K g. or part thereof.	Rs. 0.20
Table Potato (for export)	(i) All varieties and grades	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 0.05
Pulses (for export)	(i) All varieties and grades	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 0.10
Onion	(i) All varieties and grades	Per 25 Kg. or part thereof.	Rs. 0.10
Garlic	(i) All varieties and grades	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 0.15
Tendu leaves	(i) All grades	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 0.20
Tobacco	(a) Group I: Varieties:		
	(i) Fluecured Virginia strips or leaf: Grades : 1, 2, 3, 4, AF, AS, AT, FLG, LG, LBY, their composite grades and X.	Per 100 Kg. or part thereof.	Rs. 3.00
	(b) Group II: Varieties:		
	(i) Fluecured Virginia— strips, leaf or bits. Grades : LMG, MG, LBM2, B and their composite grades and Bright and Semi-bright Bits.	Per 100 Kg. or part thereof.	Rs. 1.50
	(ii) Suncured Virginia: Strips or leaf. Grades : VBT, VBR and VDR.	Per 100 Kg. or part thereof.	Rs. 1.50
	(iii) Suncured White Burley— strips or leaf Grades : WBL, WBR and WBD.	Per 100 Kg. or part thereof.	Rs. 1.50
	(iv) Suncured 'Natu ' Country— strips or leaf. Grades : CBT, CBR, CDK, CHBR, and CHD.	Per 100 Kg. or part thereof.	Rs. 1.50
	(v) Suncured Lal Chapodia: All grades	Per 100 Kg. or part thereof.	Rs. 1.50
	(vi) Suncured Black Chapodia: All grades	Per 100 Kg or part thereof.	Rs. 1.50
	(vii) Suncured Judi: All grades	Per 100 Kg. or part thereof.	Rs. 1.50
	(viii) Suncured 'Natu' Bidi tobacco flakes: Processed and Semi-processed	I. Per package of less than 50 Kg. II. Per package of 50 to 100 Kg.	Rs. 0.75 Rs. 1.50
	(ix) Suncured Motihari: All grades	Per 100 Kg. or part thereof.	Rs. 1.50
	(x) Suncured Jati : All grades	Per 100 Kg. or part thereof.	Rs. 1.50
	(xi) Suncured Calcutta: All grades	Per 100 Kg. or part thereof.	Rs. 1.50
	(c) Group III: Varieties :		
	(i) Fluecured Virginia— strips, leaf, scrap or stem: Grades : DG, DB, DDB, DBL, Dark Bits, Bright PL, Dark PL, FS, FS2 and Stems.	Per 100 Kg. or part thereof.	Rs. 0.80
	(ii) Suncured Virginia— strips, leaf, scrap or stems: Grades : VG, VPL, V-Bits, VS and VS2.	Per 100 Kg. or part thereof.	Rs. 0.80
	(iii) Suncured White Burley— Strips, leaf or bits. Grades : WB PL, WB-Bits, WBS and WBS2.	Per 100 Kg. or part thereof.	Rs. 0.80

(1)	(2)	(3)	
	(iv) Suncured 'Natu' Country— Strips, leaf, scrap or stems. Grades : CG, SB, SB2, SBM, CPL, stems, NS and NS2.	Per 100 Kg. or part thereof.	Rs. 0.80
	(v) Suncured Jutty— All grades.	Per 100 Kg. or part thereof.	Rs. 0.80
	(vi) Top leaf— All grades.	Per 100 Kg. or part thereof.	Rs. 0.80
	(vii) Suncured Jati Bispath— All grades.	Per 100 Kg. or part thereof.	Rs. 0.80
	(d) Group IV— Sample:	(i) Per packet of less than 1 Kg.	Rs. 0.40
		(ii) Per packet of 1 to 5 Kg.	Rs. 0.80
		(iii) Per packet of more than 5 Kg.	At the rates specified for the concerned grade, group and type of packing.
Fennel	(i) All grades: (a) When the grading is done by the Directorate Marketing & Inspection through its laboratory.	Per 10 Kg. of part thereof.	Rs. 0.20
	(b) When the grading is done through any State Grading Laboratory	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 0.10
Fenugreek	(i) All grades: (a) When the grading is done by the Directorate of Marketing & Inspection through its laboratory.	Per 10 Kg. or part theeof.	Rs. 0.15
	(b) When the grading is done through any State Grading Laboratory.	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 0.10
Celery Seed	(i) All grades: (a) When the grading is done by the Directorate of Marketing & Inspection through its laboratory.	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 0.20
	(b) When the grading is done through any State Grading Laboratory.	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 0.10
Coriander	(i) All grades: (a) When the grading is done by the Directorate of Marketing & Inspection through its laboratory.	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 0.15
	(b) When the grading is done through any State Grading Laboratory.	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 0.10
Cumin Seed	(i) All grades: (a) When the grading is done by the Directorate of Marketing & Inspection through its laboratory.	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 0.35
	(b) When the grading is done through any State Laboratory.	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 0.25
Ghee	(i) All grades:	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 0.50
Vegetable Oils	(i) All varieties and grades	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 0.25
Oil cakes	(i) All varieties and grades	Per 75 Kg. or part thereof.	Rs. 0.15
Creamery Butter	(i) All valeties and grades	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 0.50
Ground spices (including Currey Powder)	(i) All varieties and grades except Cardamom powder.	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 0.35
	(ii) Cardamom Powder	Per 10 Kg. or part thereof.	Rs. 2.00
All Fruits	All varieties and grades	Per case or basket of 100 Fruits	Rs. 0.10
Sugar Cane Gur (Jaggery)	All varieties and grades	Per quintal	Rs. 0.10

1	2	3	
Table potato (including seed potato) other than export	All varieties and grades	Per quintal	Rs. 0.10
Bura	All varieties and grades	Per quintal	Rs. 0.10
Eggs	All varieties and grades	Per basket of 500 eggs	Rs. 0.10
Rice	All varieties and grades	Per quintal	Rs. 0.10
Wheat Atta	All varieties and grades	Per quintal	Rs. 0.10
Pulses, other than for Export	All varieties and grades	Per quintal	Rs. 0.10

[No. F. 13-13 / 75-A—II]
PARKASH CHANDER, Under Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1978

का० आ० 3642.—सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित सारिणी के कालम (1) में उल्लिखित अधिकारियों को जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है तथा आगे यह निदेश करती है कि उपरोक्त अधिकारी उक्त सारणी में कालम (2) के तदनुरूपी इन्दराज में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों के संबंध में अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर उपरोक्त अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे अथवा उन्हें दिये गये कर्त्तव्यों का पालन करेंगे ।

सारिणी

अधिकारी का पदनाम	सार्वजनिक परिसरों की कोटियां तथा अधिकार-क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं
1	2
वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर तथा मण्डल इंजीनियर / बम्बई, बड़ोदरा, रतलाम कोटा, अजमेर, जयपुर, राजकोट तथा भाव नगर मण्डल, पश्चिम रेलवे ।	पश्चिम रेलवे के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले परिसर जो उनके अपने अधिकार-क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित हों ।

[फाइल सं० 69/डब्ल्यू 2/एल ई/13]

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 29th November 1978

S.O.3642.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Table below, being gazetted officers of Government, to be Estate Officers for the purposes of the said Act and further directs that the said officers shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on the Estate Officers by or under the said Act, within the local limits of their respective jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction.
(1)	(2)
Senior Divisional Engineers and Divisional Engineers of Bombay, Vadodra, Ratlam, Kota, Ajmer, Jaipur, Rajkot and Bhavnagar Divisions of Western Railway.	Premises under the administrative control of the Western Railway situated within the local limits of their respective jurisdiction.

[File No. 69 W2/LE/13]

का० आ० 3643.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति रेल कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. (1) ये नियम रेल कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) तृतीय संशोधन नियम, 1978 कहलायेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. रेल कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 10 में उप नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

"(5) यदि अनुशासन प्राधिकारी की राय में आरोप के सभी या किन्हीं अनुच्छेदों पर अपने निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए तथा जांच के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर नियम 6 के खण्ड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट दण्डों में से किसी दण्ड का दिया जाना वांछनीय हो तो उसके द्वारा ऐसे दण्ड दिये जाने का आदेश जारी किया जायेगा तथा रेल कर्मचारी को प्रस्तावित दण्ड के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं होगा ।

किन्तु, शर्त यह है कि ऐसे प्रत्येक मामले में जहां आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो, जांच का रिकार्ड अनुशासन प्राधिकारी द्वारा आयोग के पास उसकी सलाह के लिए अग्रेषित किया जायेगा और रेल कर्मचारी को कोई दण्ड देने से पहले आयोग द्वारा दी गयी सलाह पर विचार किया जायेगा" ।

[सं० ई० (डी० एण्ड ए०) 78/आर० जी० 6-54]

S.O. 3643.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railway Servants (Discipline and Appeal) Third Amendment, Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 10 of Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(5) If the disciplinary authority, having regard to its findings on all or any of the articles of charge and on the basis of the evidence adduced during the inquiry, is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 6 should be imposed on the railway servant, it shall make an order imposing such penalty and it shall not be necessary to give the railway servant any opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed :

Provided that in every case where it is necessary to consult the Commission, the record of the inquiry shall be forwarded by the disciplinary authority to the Commission for its advice and such advice shall be taken into consideration before making an order imposing any such penalty on the railway servant."

[No. E. (D&A)78-RG-6-54]

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर 1978

का० आ० 3644.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 19) की धारा 53 की उपधारा (1) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना सं० 75 एम० (एन०) 951/69 तारीख 12 सितम्बर 1975 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में 'बड़ी लाइन माल डिब्बे' शीर्षक के अधीन मद 1 अनुज्ञप्त अधिक मालवान की सीमा' की :

(क) उपमद (3) में उल्लिखित 'इस सीमा तक अधिक लदान करने दिया जा सकेगा' शब्दों से पहले 'लोहा और इस्पात को छोड़कर अन्य माल से' शब्द को अन्तर्विष्ट किया जाये।

(ख) उपमद (3) के बाद निम्नलिखित उपमद को अन्तर्विष्ट किया जाये, अर्थात् :—

"(4) बक्स, बी०आर०एच० तथा बी०आर०एस० माल डिब्बों को लोहा और इस्पात से इस सीमा तक अधिक लदान करने दिया जा सकेगा कि माल डिब्बों को भारवहनीयता सहित, परेषण का कुलभार, अंकित वहन क्षमता से, उसमें 2-1/2 टन भार और जोड़ दिये जाने पर भी, अधिक न हो।"

[सं० 75 एम० (एन०) 951/69]

पी० एन० मोहिले, सचिव, रेलवे बोर्ड एवं पदेन संयुक्त सचिव

New Delhi, the 2nd December, 1978

S.O. 3644.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (4) of section 53 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board) No. 75M(N) 951/69 dated the 12th September 1975, namely :—

In the said notification under the heading "A. Broad Gauge Wagons" in item "1. Extent of over loading permitted",—

(a) in sub item (3), after the words "may be overloaded", the words "by goods, other than iron and steel," shall be inserted.

(b) after sub-item(3), the following sub-item shall be inserted, namely :—

"(4) BOX, BRH and BRS wagons may be overloaded by iron and steel to the extent that the total weight of the consignment including the loading tolerance does not exceed marked carrying capacity plus 2-1/2 tonnes."

[No. 75M(N)951/69]

P. N. MOHILE, Secretary, Railway Board and ex-officio Joint Secretary

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1978

का० आ० 3645.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड 3 के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने मान्सा टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-1-79 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[संख्या 5-27/78—पी एच बी]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 7th December, 1978

S.O. 3645.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-1-1979 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Mansa Telephone Exchange, Gujarat Circle.

[No. 5-27/78-PHB]

का०आ० 3646.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड 3 के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने गौरीपुर टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-1-79 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[संख्या 5-31/76—पी एच बी]

S.O. 3646.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-1-1979 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Gauripur Telephone Exchange, N. E. Circle.

[No. 5-31/76-PHB]

का०आ० 3647.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड 3 के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने फूल मण्डी टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-1-79 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[संख्या 5-5/78—पी एच बी]

हु० अपठनीय

सहायक महानिदेशक (पी० एच० बी०)

S.O. 3647.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-1-1979 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Phul Mandi Telephone Exchange, N. W. Circle.

[No. 5-5/78-PHB]

Sd/-

Assistant Director General (PHB)

MINISTRY OF LABOUR

CORRIGENDUM

New Delhi, the 5th December, 1978

S.O. 3648.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S. O. 2033, dated the 29th June, 1978 published at page 1794 of the Gazette of India, Part-II Section 3-Sub-section (ii) dated the 8th July, 1978 in the last two lines for "1. State Council of Diploma in Mining Surveying Technical Education and Training, Orissa". read

"1. State Council of Technical Education and Training, Orissa.	Diploma in Mine Surveying."

[No. H. 11016/14/77-MI(ii)]

MEENA GUPTA, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1978

का० आ० 3649.—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान गर्त-मुख स्नान नियम, 1959 के नियम 2 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री बी० एन० सांगले, कल्याण आयुक्त, जबलपुर को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में स्थित कोयला खानों के संबंध में इन नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के सभी कृत्यों का पालन करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करती है ।

[सं० ए० 12026/3/77-मिल]

पी० के० सेन, अवर सचिव

New Delhi, the 6th December, 1978

S.O. 3649.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of rule 2 of the Coal Mines Pithead Bath Rules, 1959, the Central Government hereby appoints Shri B .N. Sangalay, Welfare Commissioner, Jabalpur as competent authority to perform all the functions of such an authority under those rules in respect of the coal mines in the States of Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Andhra Pradesh.

[No. A-12026/3/77-M. II]

P. K. SEN, Under Secy.

New Delhi, the 7th December, 1978

S.O. 3650.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Calcutta Port Trust, Calcutta and their workmen which was received by the Central Government on the 5th December, 1978.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 15 of 1977

PARTIES :

Employers in relation to the management of Calcutta Port Trust, Calcutta,

AND

Their Workmen

PRESENT :

Sri Justice S. K. Mukherjea—Presiding Officer.

APPEARANCES

On behalf of employers—Shri D. K. Mukherjee, Labour Officer.

On behalf of Workmen—Sri P. K. Dutta, General Secretary of the Union, with Sri Safiruddin Ahmed, Jt. Secretary.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Port & Dock

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by their order No. L-32011(6)/77-D. IV(A) dated the 2nd June, 1977, referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Calcutta Port Trust, Calcutta and their workmen, to this Tribunal for adjudication. The reference reads :

"Whether the management in relation to Calcutta Port Trust, Calcutta are justified in refusing tiffin allowance to Shri Sadhan Kumar Dey, Radiographer, Sri S. N. Gupta, X-Ray Technician, Shri P. Tiwari and Sisu Bala Karmakar, X-Ray Attendants for the days they come in contact with the T. B. Patients : If not, to what relief are they entitled ;"

2. The Trustees of the Port maintain two hospitals for their employees, namely, (i) Centenary Hospital, and (ii) Dock Hospital. In the Dock hospital there is a Chest clinic and an isolation ward for treatment of employees suffering from Tuberculosis. The Trustees also maintain a number of reserved T. B. beds in several T. B. hospitals. There are 15 such beds in Kiron Shankar Roy T. B. Hospital, four beds in Kanchrapara T. B. Hospital and six beds in the hospital of the Tuberculosis Association. The present dispute has been raised by or on behalf of the Radiographer, X-Ray technician and two X-ray Attendants attached to the dock hospital.

3. It will not be out of place to go a little into the history of grant of tiffin allowance to certain categories of workmen attached to the Dock hospital. The demand for grant of a tiffin allowance was first raised by the Calcutta Port Shramik Union in 1959. The Commissioners for the Port of Calcutta by Resolution No. 1414 of October 29, 1959 sanctioned payment of tiffin allowance to the class III and class IV employees deputed to work in the isolation ward in the Dock hospital for the period they were so deputed to work. Thereafter the benefit of tiffin allowance was extended to class III and class IV staff attached to the Chest clinic of the Dock hospital. By Resolution No. 994 passed on July 27, 1964, the benefit of tiffin allowance was further extended to the Dhobies attached to the Dock hospital who were required to wash the linen of the patients of the Isolation Ward more or less on a continuous basis, with effect from November 11, 1970. It appears that the Chairman approved payment of tiffin allowance with effect from October 30, 1972 to a cook-mate who attends the Isolation ward of the Dock hospital.

4. The Calcutta Port Shramik Union pursued their demand for tiffin allowance, amongst others, to the nursing staff, pharmacists, Dressers, Laboratory assistants, X-ray technicians, Dhobies and Stretcher bearers of the Dock hospital at the Government level in the Ministry of Transport. At a meeting held at Delhi in March, 1971, Sri O. Maheepati, Deputy Chief Labour Commissioner (Central) was requested to arbitrate on these demands. By his Award, Sri Maheepati rejected the demand except in the case of members of the nursing staff who were deputed to work in the Isolation Ward.

5. The union however raised the demand for tiffin allowance for the Dock hospital staff attending isolation ward. The Union also by a letter dated June 7, 1974 raised the issue before the Regional Labour Commissioner (Central) Calcutta. The conciliation proceedings having ended in failure, the Government by an order dated 14th January, 1975 referred the demand of the stretcher-bearers attached to the Dock hospital for tiffin allowance for the days they come in contact with T.B. patients in the isolation ward to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in Reference No. 6 of 1975. The Tribunal presided over by my predecessor Sri Justice E. K. Moidu answered the reference in favour of the stretcher-bearers by holding that they are entitled to the tiffin allowance for the days on which they carry patients from the Dock hospital to other T. B. hospitals or bring them back to the Dock hospital as well as on those days on which they carry patients to and from Isolation Ward of the Dock hospital and the Chest clinic or other places for treatment.

6. Thereafter the union raised a fresh dispute in respect of the Radiographer, the X-Ray technician, and the X-ray attendants attached to the Dock hospital for grant of tiffin allowance. That is the dispute which is the subject matter of this reference.

7. The union which has sponsored the dispute has stated in paragraph 9 of its written statement that the Radiographer, the X-ray technician, and the X-ray attendants came in close contact with the T.B. patients during th ecourse of their duties and as such they need extra nourishment for which they should be paid tiffin allowance in respect of the days on which they handle T. B. patients for X-ray examination. In paragraph 10 of its written statement the Union has submitted that the communication of infectious disease does not require long hours or continuous contact with patients. The extra food needed is a protective measure required by those who come in close contact with T.B. patients and denial of the tiffin allowance to the X-ray staff is not justified.

8. The Port Trust has submitted by its written statement that the principles for granting tiffin allowance to the Class III and class IV employees attached to the Dock hospital which were arrived at through discussions and negotiations. Arbitration and Tribunal Award are that class III and class IV employees continuously deputed to work in the isolation ward in the Dock hospital would be paid tiffin allowance for the period they are so deputed to work in the said Ward and for accompanying T.B. patients when they are sent to and from different hospitals in Ambulance, or for washing linen of such patients of the isolation ward. It was also submitted that any Radiology unit has to take X-ray photo of cases which may ultimately prove to be tubercular as also of known cases of T. B. patients. In the course of taking such X-ray, it requires two to three minutes for one patient to be X-rayed. The radiographer, the X-ray technician and the attendants do not in any way remain in contact with the T.B. patients continuously for long hours; that as a matter of fact all categories of staff belonging to the medical department have to come in contact with T.B. and other infectious patients temporarily either before or after diagonosis. The Port Trust maintains that in these circumstances the demand for tiffin allowance for radiographer, X-ray technicians and X-ray attendants is not justified in principle.

9. Among the concerned workmen, Sri Sadhan Kumar Dey, the Radiographer alone gave evidence. He deposed that an ordinary T. B. patient comes from the Isolation ward to the x-ray unit in the hospital. He has to place the patient in the proper position in the X-ray stand. If a patient comes in a stretcher, the patient is undressed by him with the help of attendants. He has also to take the x-ray photographs. In case of patient is not able to hold his breath at the time of taking X-ray photograph, the attendant helps him so to do. If the attendant is unable to do so, he has to do it personally. T.B. patients for X-ray photographs come every day. Record is kept of such patients. They come from isolation ward, from chest clinic and from the hospital dispensary.

10. The Radiographer, after passing the Higher Secondary School Examination, qualified for a certificate from Post Graduate Medical Education and Research Institute, Calcutta. In cross-examination, he stated that apart from T.B. patients, patients of other descriptions also come to him from hospital or from out-door dispensaries for x-ray photographs. Among them are orthopaedic and surgical cases as well as cases of chest diseases. All chest caes are not T.B. cases. Sometimes suspected cases of tuberculosis also come to him for x-ray examination. Patients walk upto the stand and take their position and thereafter he has to correct the position. From the time the patient takes position in the stand upto the time the photograph is taken, the process takes about four minutes. On the average, the radiographer has to deal with 50 T.B. cases in a month. The distance from the x-ray machine to the stand is approximately five feet. The patient does not have to stand up in every case. Sometimes photographs are taken of the patient in a sitting position. In case a patient is unable to sit up, he has to be x-rayed lying in bed.

11. On behalf of the management Dr. Amarendra Nath Mukherjee, Registrar, Dock hospital gave evidence. Dr. Mukherjee is an M.B., B.S. and an M.D. of University of Calcutta. He has also qualified for a diploma in Tuberculosis and Chest diseases. He is a Fellow of the Chest College of Physicians, U.S.A. He has been working since 1955 in the Dock hospital. He has also worked in the Chest clinic since its inception on 14th May, 1963. There is a chest clinic only in the Dock hospital. There are x-ray units both in the Dock hospital and in the Centenary hospital. The X-ray and chest units are separate units. There is one Radiographer in such hospital. Pulmonary tuberculosis cases are referred to the x-ray unit from Isolation ward, Chest clinic, other out-door units in Dock hospital and from dispensaries. On an average 50 T.B. cases go to the x-ray unit of the Dock hospital every month. The radiographer's main duty is to operate the x-ray machine and other medicotherapeutic instruments. It is also his duty to keep records of stores and stocks. To take x-ray photographs is also a part of his duty. The x-ray technician processes and develops the x-ray plates. Normally x-ray technicians do not attend patients when they are brought to the X-ray unit. It may, of course, happen sometimes that on account of the absence of the radiographer, the technician has to do the work of the radiographer under the supervision of the radiologist but such instances are few and far between. The attendants uncover chests of patients. They accompany patients to the x-ray stand. They assist the radiographer in placing the patient in position in the stand. Attendants also carry exposed x-ray plates from the x-ray room to the dark room. There is a male attendant and a female attendant. Normally the x-ray technicians do not come in contact with T.B. patients. The instrument does not require cleaning. Attendants have to clean basins. Basins are not in the x-ray room and are not intended for patients. There is basin in the dark room and there is also one in the Doctor's room. Basins are in use for processing the X-ray plates.

12. Dr. Mukherjee deposed that in the prevention of tuberculosis, nutrition plays an important part but there are also other facts such as sanitation, pure air, good ventilation, etc. These are matters of common knowledge. He further deposed that a T.B. patient becomes a source of infection only when he emits in his sputum acid-fast bacilli. All T. B. patients do not emit acidfast bacilli all the time. When they emit acid-fast bacilli they are called open cases. Only open cases can infect. Sometimes closed cases may start emitting acid-fast bacilli. Then they become open cases. When the case is not open, the patient does not infect. A closed case may become open because of certain reasons, as for example, superinfection that is when the patient is heavily infected with more bacilli or by reason of the bacilli developing drug resistance. Similarly, an open case may become closed. The chance of infection depends on the proximity of patients of the open type, the duration of the exposure and the concentration of the bacilli in the patient's sputum. In urban areas like Calcutta, the incidence of tuberculosis is fairly high. In the usual course, citizens are exposed to infection. X-ray technicians do not have much to do with patients in the sense that they do not come in the proximity of the patient. They are concerned by and large with developing and processing of exposed x-ray plates. The radiographer and the attendants come in proximity of the patients. Dr. Mukherjee stated from his experience as also on the basis of records that out of 50 cases which go to the x-ray unit every month, only about 10 cases are open cases. In cross-examination he said that there are four rooms the X-ray unit, one for the radiologist, one for record purposes, one for X-ray machine and one used as a side room. The area of the room where the X-ray plant operates is approximately 10'x12'. The X-ray technician is occupied in processing x-ray plates in the dark room adjoining the x-ray plant. It also happens that some time when he is free he comes to the x-ray plant room. Moreover, the x-ray technician has to enter the dark room through the x-ray room. There is no waiting room for the x-ray technician and the attendants. There is no arrangement to disinfect the x-ray room after a day's work is over. Cleaning is done by sweeper. There is daily cleaning with water. Disinfectants like phenyle etc. are used sometimes. Liquid soap or washing soda is used to clean the x-ray room at intervals. Fumigation is not done in the x-ray room in the Dock hospital or other hospital for fear of damaging the sophisticated instruments. By disinfection Dr. Mukherjee understood fumigation.

13. A satisfactory feature of the case is that the evidence of the radiographer and of Dr. Mukherjee substantially agree. There is no dispute that the number of T.B. cases which go to the x-ray unit every month is 50 on the average; that the entire process of taking the x-ray photograph takes nearly four minutes. There is no dispute as to the duties of the radiographer, x-ray technician and the attendants. Neither the X-ray technician nor the attendants have given evidence. The nature of their respective duties has been brought out clearly by Dr. Mukherjee and his evidence has not been contradicted. The medical part of the evidence given by Dr. Mukherjee has been of assistance to me. Out of fifty T.B. cases which go to the x-ray unit every month, only ten are open cases. The entire process of x-ray examination takes nearly four minutes. Only open cases are infectious. Therefore,

in those ten cases, there is exposure to infection for 40 to 50 minutes in a month. In other words, the duration of the exposure is roughly a minute and a half per day. There is evidence that almost every day a T.B. case though not necessarily an open case, comes to the x-ray unit. It has also to be remembered that the intensity of the exposure is not uniform. It varies with the distance, that is to say, with the distance of the subject of the exposure from the object, the nature of physical contact, the duration of such contact and other factors. For example, sneezing or coughing on the part of the patient at the relevant point of time will increase the intensity of the exposure. It appears that before Sri Justice B. K. Moidu who decided the reference on stretcher-bearers, no statistical evidence was given as to the number of T.B. patients. Moreover, the distinction between open and closed cases was not brought out. The observation of the learned Presiding Officer that it requires only a second for a person to be infected by a T.B. patient, if one comes in contact with the patient is not in dispute. Infection may be instantaneous but the factor which has to be considered is the degree of risk involved in the duties of the concerned workmen. Normal risk of infection is always there even when one is not working in a hospital or in a medical unit. The risk of infection, or in other words, the probability of infection will very with the duration of continuity of the exposure to a T.B. patient of an open type, the proximity of the T.B. patient and the concentration of the bacilli in the patient's sputum as pointed out by Dr. Mukherjee. A person exposed to a T.B. patient of the open type casually or for a very brief period stands a lesser risk of infection than a person who is exposed to such a patient for an appreciable stretch of time. The proximity of the patient and physical contact are also factors which increase the risk. That does not mean that a person who is casually exposed or is exposed for a short time does not stand the risk of infection. He does. So does a multitude of citizens knowingly or unknowingly. The question, as I have pointed out, is one of degree. If one is to judge by these tests it seems to me that the risk of infection in the case of the X-ray technician is very little. By and large, he handles instruments and is concerned with processing and developing of exposed x-ray plates. He is not directly concerned with patients except very occasionally, if need be, and that also only at a certain stage. It was pointed out that for the purpose of ingress and egress he has to pass through the x-ray room where T.B. patients are brought in for the purpose of taking x-ray photographs. As I have pointed out, on an average there is an infectious T.B. patient in the x-ray room for a minute and a half in a day, or to be more concrete, there is one open case every third day, involving exposure for four or five minutes. The probability of the x-ray technician passing through the x-ray room during those brief moments is not such as to make it a factor. As regards the Radiographer, he is exposed to infection, say, for a minute half on the average, everyday. Out of that minute and a half he is not in proximity of the patient all the time. He comes in proximity of the patient only when he places the patient in position in the stand with the help of the attendant. He may have to, again, on occasions help the patient hold his breach or help him uncover his chest if the attendant is unable to render full assistance by himself. These are casual and occasional cases. By and large, he comes in close proximity of the patient only when he places the patient in position in the stand with the assistance of the attendant. That is a process which, it seems to me, takes a small fraction of the total time. Such exposure therefore, is, in reality, for very much less than a minute and a half a day. Taking the x-ray photograph from a distance of 5' also exposes him to the patient for a fraction of the total time but the process is not, in my opinion, such as to make the radiographer a medical risk. The entire situation has to be judged against the background of normal exposure to known and unknown T.B. patients which all persons working in out-door clinics and in different departments of the hospital have to undergo. It must also be remembered that members of the public at large, as for example, persons travelling in overcrowded public transports have to undertake normal exposure risks.

14. On an anxious consideration of the matter I am of opinion that in the facts and circumstances of this case the Radiographer and the x-ray technicians are not entitled to payment of tiffin allowance.

15. As regards the attendants, I feel that theirs is a borderline case. There is a male and a female attendant. The male attendant attends to the male and the female attendant attends to the female patients. The duration of exposure is therefore proporionately less in the case of the attendants, depending on the number of male or female patients of the open type. Be that as it may, the attendants come in close proximity and physical contact of T.B. patients for a while. They have to uncover patients' chests, take them to the stand, place them in position, assist the Radiographer, conduct the patients back from the stand and help them put on their garments. As there is no evidence of the proportion of male patients to female patients, it is not possible to make any distinction between the two attendants. In any case, having regard to the nature of their duties, I feel, their claim for tiffin allowance should be conceded.

16. In the result, I answer the reference in the following terms : the management in relation to the Calcutta Port Trust, Calcutta is justified in refusing tiffin allowance to Sri Sadhan Kumar Dey, Radiographer and Shri S. N. Gupta, the x-ray Technician. The management is not justified in refusing tiffin allowance to Sri P. Tiwari and Sisu Bala Karmakar, X-ray Attendants for the days they come in contact with the T.B. patients. Only Sri P. Tiwari and Sisu Bala Karmakar, the X-ray Attendants are entitled, by way of relief allowance for the days they come in contact with the T.B. patients.

Dated, Calcutta,
The 22nd November, 1978.

Sd/-
S. K. MUKHERJEA, Presiding Officer.

[No. L-32011(6)/77-D. IV(A)]
NAND LAL, Desk Officer.

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1978

का० आ० 3651.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जेनिथ एजेंट्स सर्विसेज, एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, 46, बजाज भवन, चौथा फ्लोर, नरीमन पाइंट, मुम्बई-21, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 अक्टूबर, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35018(104)/78-पी० एफ० 2]

New Delhi, the 7th December, 1978

S.O. 3651.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Zenith Agents Services and Exports Limited, 46, Bajaj Bhavan, 4th Floor, Nariman Point, Bombay-21, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of October, 1977.

[No. S. 35018 (104)/78-PF. II]

का० आ० 3652.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मैरिन मेटल कोट (प्राइवेट) लिमिटेड, 509, अरुण चैम्बर्स, मेन ताड़देव रोड, मुम्बई-34, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19 के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 सितम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35018/94/78—पी० एफ० 2]

S.O. 3652.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Marine Metal Coat (Private) Limited, 509, Arun Chambers, Main Tardeo Road, Bombay-34, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1976.

[No. S. 35018/94/78-PF. II]

का० आ० 3653.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बोनकॉन इंजीनियर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, रेडी मनी टैरेस, तीसरा फ्लोर, 167, डा० एनी बेसंट रोड, वर्ली, मुम्बई-18, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35018/99/78—पी० एफ० 2]

S.O. 3653.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Boncon Engineers (Private) Limited, Ready Money Terrace, 3rd Floor, 167, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-18, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1978.

[No. S. 35018/99/78-PF. II]

का० आ० 3654.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दीपक प्लास्टिक्स, 125, जोगानी इण्डस्ट्रियल एस्टेट, सेनापति बापत मार्ग, दादर ,मुम्बई-28, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 28 फरवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० ० 2]

S.O. 3654.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Deepak Plastics, 125, Jogani Industrial Estate, Senapati Bapat Marg, Dadar, Bombay-28, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the twentyieghth day of February, 1977.

[No. S. 35018/97/78-PF. II]

का० आ० 3655.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दि लोकमित्र सहकारी प्रिंटिंग एण्ड पब्लिशिंग सोसाइटी लिमिटेड, ए-18, श्रीराम इण्डस्ट्रियल एस्टेट, जी० डी० अम्बेकर रोड वाडला, मुम्बई-31, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35018/96/78-पी० एफ० 2]

S.O. 3655.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. The Lakmitra Sahakari Printing and Publishing Society Limited, A-18, Shriram Industrial Estate, G.D. Ambekar Road, Wadala, Bombay-31 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1977.

[No. S. 35018/96/78-PF. II]

का० आ० 3656.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नागार्जुन प्रिंटिंग वर्क्स, 1-1-60, इफ्तिखार मैंशन, मुशिदाबाद, हैदराबाद, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थाप को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 मार्च, 1974 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019 (220)/78—पी० एफ० 2]

S. O. 3656.—Whereas it ppears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Nagarjuna Printing Works, 1-1-60, Iftekhar Mansion, Mursheedabad Hyderabad, have agreed that the provisions of the Empolyees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicab'e to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1974.

[No. S. 35019(220)/78-PF. II]

का० आ० 3657.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री शान्तिविहार, मुख्य सड़क, श्रीककुलम, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019 (221)/78-पी० एफ० II]

S. O. 3657.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sri Santivihar Main Road, Srikakulam, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of December, 1976.

[No. S. 35019(221)/78-PF. II]

का० आ० 3658.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री कृष्ण विलास काफी होटल, राजम, श्रीककुलम जिला, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019 (236)/78-पी० एफ० II]

S. O. 3658.—Whereas it apppears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sri Krishana Vilas Coffee Hotel, Rajam, Srikakulam District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of December, 1976.

[No. S. 35019 (236)/78-PF. II]

का० आ० 3659.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आरसीकेरे तालुक एग्रिकलचरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, आरसीकेरे, हसन जिला, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019 (238)/78-पी० एफ० II]

S. O. 3659.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Arasikere Taluk Agricultural Produce Marketing Cooperative Society Limited, Arasikere, Hassan District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1978.

[No. S. 35019)238)/78-PF. II]

का० आ० 3660.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री महाराजा इग्जिबिटर्स, सलाबतपुरा, महात्मावाडी, सूरत, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 मार्च, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019 (235)/78—पी० एफ० II]

S. O. 3660.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shree Maharaja Exhibitors, Salabatpura, Mahatmawadi, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies, the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of March, 1978.

[No. S. 35019(235)/78-PF. II]

का० आ० 3661.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री वी० वी० वसु, दि कन्ट्रैक्टर सेंट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन वेस्ट हिल, कालीकट, काचेरी ग्राम कोझीकोड तालुक, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 सितम्बर, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 36019 (228)/78-पी० एफ० II]

S.O. 3661.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sri V.V. Vasu, the Contractor Central Ware Housing Corporation West Hill, Calicut, Kacheri Village Kozhikode Taluk, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1978.

[No. S. 35019(228)/78-PF. II]

का० आ० 3662.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डेक्कन पेपर एण्ड बोर्ड्स, 175/1, माउंट रोड, मद्रास-2, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जून, 1974 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(231)/78-पी० एफ०II(i)]

S.O. 3662.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Deccan Paper and Boards, 175/1, Mount Road, Madras-2, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1974.

[No. S. 35019(231)/78-PF-II(i)]

का०आ० 3663.—यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ईस्टर्न क्रोम टैनिंग कार्पोरेशन, नं० 19ए, वेपरी हाई रोड, मद्रास-3 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 फरवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं०एस० 35019(224)/78-पी०एफ II(i)]

S.O. 3663.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Eastern Chrome Tanning Corporation, No. 19-A Vepery High Road, Madras-3, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of February, 1977.

[No. S. 35019(224)/78-PF-II (i)]

का०आ० 3664.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इलेक्ट्रोमैटिक टैकनिक, 12, जेसौर रोड दमदम कैंट, कलकत्ता-28, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अगस्त, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35017(60)/78-पी०एफ० II]

S.O. 3664.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Elektromatic Technik, 12, Jessore Road, Dum Dum Cantt Calcutta-28, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1977.

[No. S. 35017/60/78-PF. II]

का०आ० 3665.—यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एक्सप्लोरर, इंजीनियर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, 13/1सी, प्रियानाथ मलिक रोड, कलकत्ता-26, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 नवम्बर, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35017(62)/78-पी०एफ० II]

S.O. 3665.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Explorer Engineers (Private) Limited, 13/1C, Priyanath Mallick Road,

Calcutta-26, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers confered by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1977.

[No. S. 35017/62/78-PF. II]

का०आ० 3666.—यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स घोष, बोष एण्ड एसोसिएट्स (प्राइवेट) लिमिटेड, 8, हैरिंगटन मैनसन, 8, हो०चि० मिंह सरानी, कलकत्ता-71 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 नवम्बर, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35017(59)/78-पी०एफ० II]

S.O. 3666.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ghosh, Bose and Associates (Private) Limited, 8, Harrington Mansion, 8, Ho-Chiminh Sarani, Calcutta-71, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1977.

[No. S. 35017/59/78-PF. II]

का०आ० 3667.—यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मशीनो कार्पोरेशन, 11-ए, क्रिट्टी बाश मुखर्जी रोड, कलकत्ता-4, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 मार्च, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35017(63)/78-पी० एफ II]

S.O. 3667.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Machino Corporation, 11A Krithy Bash Mukherjee Road, Calcutta-4, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers confered by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of March, 1978.

[No. S. 35017/63/78-PF. II]

का०आ० 3668.—यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आर० एम० डी० सी० पैकेजिंग (प्राइवेट) लिमिटेड, 70-71, वर्ली एस्टेट, मुम्बई-18, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35018(98)/78-पी०एफ० II(i)]

S.O. 3668.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs R.M.D.C Packaging (Private) Limited, 70-71, Worli Estate, Bombay-400018 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1977.

[No. S. 35018/98/78-PF. II(i)]

का०आ० 3669.—यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री निवास केमिकल्स, शेड नं० 22, एम० आई० डी० सी० शेड्स, अम्बरनाथ इण्डस्ट्रियल एरिया, केमिकल जोन, अम्बरनाथ जिला ठाणा, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 अक्टूबर, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35018(100)/78-पी०एफ० II(i)]

S.O. 3669.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Srinvas Chemicals, Shed No. 22, MIDC Sheds, Ambernath Industrial Area, Chemical Zone, Ambernath, District Thana have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of October, 1977.

[No. S. 35018/100/78-PF.II(i)]

का०आ० 3670.—यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स माइसोप्लास्टिका (प्राइवेट) लिमिटेड, 24-ए, जौली मेकर चैम्बर्स नं० 1 नारीमन प्वाइंट मुम्बई-21, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35018(103)/78-पी०एफ० II]

हंस राज छाबड़ा, उप सचिव

S.O. 3670.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mysoplastica (Private) Limited, 24-A, Jolly Maker Chamber No. 1, Nariman Point, Bombay-21, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1978.

[No. S. 35018(103)/78-PF. II]
HANSRAJ CHHABRA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1978

का०आ० 3671.—केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग 1 में वुलफ्राम खान में नियोजन जोड़ती है, जिसके ऐसा करने के आशय की सूचना तारीख 29 अप्रैल, 1978 के राजपत्र पृष्ठ 1223 पर प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1249, तारीख 7 अप्रैल, 1978 द्वारा पहले ही दी जा चुकी है।

[सं० एस० 32025(38)/76-डब्ल्यू० सी(एम० डब्ल्यू०)]

अशोक नारायण, उप सचिव

New Delhi the 7th December, 1978

S.O. 3671.—In exercise of the powers conferred by section 27 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government hereby adds to Part I of the Schedule to that Act the employment in Wolfram mines, notice of its intention to do so having already been given by the notification of Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1249, dated the 7th April, 1978 published at page 1223 of the Official Gazette dated 29th April, 1978.

[No. S. 32025(38)/76-WC(MW)]
ASHOK NARAYAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1978

का० आ० 3672.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखण्ड (vi) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1824 तारीख 14 जून, 1978 द्वारा सिक्युरिटी पेपर मिल होशंगाबाद को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 18 जून, 1978 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः, अब, औद्योगिक अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखण्ड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को 18 दिसम्बर, 1978 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा सेवा घोषित करती है।

[सं० एस० 11017 / 10/ 78- डी० 1 (ए०)]

New Delhi, the 8th December, 1978

S.O. 3672.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. 1824 dated the 14th June, 1978, the Security Paper Mill, Hoshangabad, to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 18th June, 1978;

And whereas the Central Government is of the opinion that the public interest requires the extension of the said period by a further period of six months ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act for a further period of six months from the 18th December, 1978.

[No. S. 11017/10/78/DI(A)]

का० आ० 3673.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2, के खण्ड (द) के उपखण्ड (vi) के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1826 तारीख 14 जून, 1978 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (बब) में यथोपरिभाषित बैंकिंग कम्पनी द्वारा चलाए जा रहे बैंकिंग उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 29 जून, 1978 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 29 दिसम्बर, 1978 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं० एस० 11017/12/78- डी० 1 (ए०)]

एल० के० नारायणन्, डेस्क अधिकारी

S.O. 3673.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required, had in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. 1826 dated the 14th June, 1978 the Banking Industry carried on by a banking company as defined in clause (bb) of section 2 of the said Act to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 29th June, 1978;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 29th December, 1978.

[No. S. 11017/12/78/DI(A)]

L. K. NARAYANAN, Desk Officer

का० आ० 3674.—मैसर्स ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड की पोइडीह कोलियरी सीतारामपुर उप क्षेत्र दिशेरगढ़ क्षेत्र के प्रबन्धतंत्र और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व कोयला मजदूर कांग्रेस (एच० एम० एस०) आसनसोल करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और उक्त प्रबंधतंत्र और उनके कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यस्थ के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम करार को, जो उसे 30-11-1978 को मिला था, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है ?

(करार)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन)

पक्षकारों के नाम :

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले	1. श्री एस० एम० असरफ, सहायक मुख्य कार्मिक अधिकारी, मैसर्स ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड का दिशेरगढ़ क्षेत्र, बोराचक हाउस, डाकघर सीतारामपुर जिला बर्दवान।
	2. श्री जैड़ रहमान, प्रबन्धक, पोइडिह कोलियरी, डाकघर सीतारामपुर (बर्दवान)।
कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले	1. प्रो० विनय कुमार महामंत्री, कोयला मजदूर कांग्रेस (एच० एम० एस०) गोराई मेंशन, जी०टी० रोड, आसनसोल।
	2. श्री एस० के० पांडे, मंत्री।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित विवाद को श्री डी० वी० रामचन्द्रन, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय) आसनसोल के माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है :—

1. विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त विषय :	1. क्या पोइडीह कोलियरी के भूमिगत लोडरों की पहली मई, 1975 को मजदूरी / निर्वाह मजदूरी का भुगतान करने की मांग न्यायोचित है ? यदि हां तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ?
	2. क्या श्रमिक 17 अगस्त से 21 अगस्त, 1978 तक की हड़ताल की अवधि के लिये कोई मजदूरी पाने के हकदार है ?
2. विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें अंतर्वलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है।	1. मैसर्स ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, डाकघर सीतारामपुर (बर्दवान) के दिशेरगढ़ क्षेत्र के रामपुर उप-क्षेत्र के अधीन पोइडीह कोलियरी के प्रबन्धतंत्र।
	2. महामंत्री, कोयला मजदूर कांग्रेस (एच० एम० एस०) रजिस्ट्रेशन नं० 11382, गोराई मेंशन जी० टी० रोड, आसनसोल जिला बर्दवान।
3. यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो तो उसका नाम	महामंत्री, कोयला मजदूर कांग्रेस (एच० एम० एस०) गोराई, मेंशन, जी० टी० रोड, आसनसोल।
4. प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या	लगभग 1115
5. विवाद द्वारा प्रभावित या सम्भावतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या	लगभग 200

हम यह करार भी करते है कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर आबद्ध कर होगा।

मध्यस्थ अपना पंचाट 120 (एक० सौ और बीस) दिन की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा। यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम के लिए निदेश स्वतः रद्द हो जाएगा और हम नए मध्यस्थम के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे।

ह०/-(विनय कुमार) ह/- एस० एम० असरफ
तारीख 21-8-78

(कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले) (नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले साक्षी)

मैं विवाचक बनने के लिये सहमत हूं। 1. अपाठ्य
ह०/- डी० वी० रामचन्द्रन, 2. अपाठ्य
21-8-78

क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), आसनसोल

[संख्या एल०-19013/(4)/78-डी० 4 (बी०)]
भूपेन्द्र नाथ, डेस्क अधिकारी

S.O. 3674. Whereas an industrial dispute exists between the management of Poidih Colliery, Sitarampur Sub-Area of Dishergarh Area of Messrs Eastern Coalfields Limited and their workmen represented by Koyla Mazdoor Congress (HMS) Asansol ;

And whereas the said management and their workmen have by a written agreement in pursuance of the provisions of sub-section (i) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) agreed to refer the said dispute to arbitration of the person mentioned therein and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government ;

Now therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (3) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement which was received by it on the 30th November, 1978.

AGREEMENT

(Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947)

BETWEEN

Representing the employers.—1. Shri S. M. Asraf, Asstt. Chief Personnel Officer, Dishergarh Area of M/s. Eastern Coalfields Ltd., Borachak House, P.O. Sitarampur, Distt. Burdwan. 2. Mr. Z. Rahaman, Manager, Poidih Colliery Sitarampur (Burdwan).

Representing the workmen :—1. Prof. Vinay Kumar, Genl. Secretary, Koyla Mazdoor Congress (HMS), Gorai Mansion, G. T. Road, Asansol. 2. Shri S. K. Pandey, Secretary.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of D. V. Ramachandran, Regional Labour Commissioner (Central) Asansol.

(i) Specific matters in disputes :

(1) "Whether the demand of the Underground Loaders of Poidih Colliery for payment of wages/full back wages on 1st May, 1978 is justified ?

If so, what relief the workmen are entitled to ?"

(2) "Whether the workmen are entitled for any wages for the Strike period from 17th August, to 21st August, 1978 ?"

(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved :

(1) The management of Poidih Colliery, Under Sitarampur Sub-Area of Dishergarh Area, M/s. Eastern Coalfields Limited, P.O. Sitarampur (Burdwan).

(2) The General Secretary, Koyla Mazdoor Congress (HMS) Registration No. 11382), Gorai Mansion, G. T. Road, Asansol, Distt. Burdwan.

(iii) Name of the workman in case he himself is involved in the dispute or the name of the Union, if any, representing the workmen in question.

Representing the workmen.—The General Secretary, Koyla Mazdoor Congress (HMS) Gorai Mansion, G. T. Road, Asansol.

(iv) Total No. of workmen employed in the undertaking effected :

About 1115.

(v) Estimated No. of workmen effected or likely to be affected by the—about 200.

We further agree that decisions of the Arbitrator shall be binding on us.

The arbitrator shall make his award within a period of 120 (one hundred and twenty days) or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Sd/- (Vinay Kumar)

(Representing the workmen)

I consent to become Arbitrator.

Sd./- D. V. Ramachandran

Regional Labour Commissioner (C) Asansol.

Sd/-(Shri S. M. Asraj) Dt. 21-8-78

(Representing the employer)

Witnesses :

1. Sd./- Illegible

2. Sd/-Illegible Dt. 21-8-78

[No. L-19013(4)/78-D. IV(B)]

BHUPENDRA NATH, Desk Officer

आदेश

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1978

का० आ० 3675.—इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद श्री प्रीतपाल सिंह, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, लुधियाना के समक्ष लंबित है;

और उक्त श्री प्रीतपाल सिंह की सेवाएं अब उपलब्ध नहीं है;

और यूनियन ने अनुरोध किया है कि यह मामला हिमाचल प्रदेश में अन्तरित कर दिया जाए और ऐसा करना उनकी सुविधा और वित्तीय दशा के अनुरूप होगा।

और केन्द्रीय सरकार यूनियन के इस आधार को युक्तियुक्त समझती है;

और प्रबन्धतंत्र ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है और उसकी आपत्ति को ध्यान में रखा गया है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 33ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री शमशेर सिंह कंवर होंगे, जिनका मुख्यालय धर्मशाला में होगा और उक्त श्री प्रीतपाल सिंह के समक्ष लम्बित उक्त विवाद से सम्बद्ध कार्यवाहियों को वापस लेती है और श्री शमशेर सिंह कंवर, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, धर्मशाला, को, उक्त कार्यवाहियों के निष्पादन के लिए इस निदेश के साथ अन्तरित करती है कि उक्त अधिकरण आगे कार्यवाहियां उसी प्रक्रम से करेगा जिस पर वे उसे अन्तरित की गई हैं तथा विधि के अनुसार उनका निष्पादन करेगा।

अनुसूची

क्रम सं०	विवाद के पक्षकार	औद्योगिक विवाद का निर्देश और तारीख
1	2	3
1.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर और उनके कर्मकार जिनका प्रतिनिधित्व साल्ट माइंस लेबर यूनियन, डूंगर मंडी ने किया है।	एल०-29011/97/75-डी० 3(बी) तारीख 30 अप्रैल, 1976।

[सं० एल० 29025/1/78-डी० 3(बी)]

ORDER

New Delhi, the 12th December, 1978

S. O. 3675.—Whereas the industrial dispute specified in the Schedule hereto annexed is pending before Shri Pritpal Singh, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Ludhiana;

And whereas, the services of the said Shri Pritpal Singh are no longer available;

And whereas, the Union has requested that the case should be transferred to Himachal Pradesh to suit their convenience and financial condition;

And whereas, the Central Government consider the stand taken by the Union as reasonable;

And whereas, the Management have objected to this proposal and their objection taken into account;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and sub-section (1) of section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Shamsher Singh Kanwar shall be the Presiding Officer with headquarters at Dharamsala and withdraws the proceedings in relation to the said dispute pending before the said Shri Pritpal Singh and transfers the same to Shri Shamsher Singh Kanwar, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Dharamsala, for the disposal of the said proceedings with the direction that the said Tribunal shall proceed with the proceedings from the stage at which it is transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Sl. No.	Parties to the dispute	Reference No. and date of Industrial dispute
1	2	3
1.	Management of Hindustan Salts Ltd., Jaipur and their workmen represented by the Salt Mines Labour Union, Drang, Mandi.	L-29011/97/75-D.III.B dated the 30th April, 1976.

[No. L-29025/1/78-D. III. B]

आदेश

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1978

का० आ० 3676.—इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद श्री के० सीथारामा राव, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, मद्रास के समक्ष लम्बित पड़ा है;

और उक्त श्री सीथारामा राव की सेवाएं अब उपलब्ध नहीं रही हैं;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7ए और धारा 33ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री सेल्वारत्नम होंगे, जिसका मुख्यालय मद्रास में होगा और वह 1976 की रिट अपील संख्या 90 के संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उक्त विवाद के संबंध में सम्पूर्ण मामले पर नये सिरे से विचार करेंगे और कानून के अनुसार उक्त मामले का निपटान करेंगे।

अनुसूची

इस मंत्रालय के आदेश संख्या 12(36)/70-एल०आर०-4 तारीख 22-1-1971 द्वारा मैसर्स डालमिया मैगनेसाइट कारपोरेशन, सेलाम के श्रमिकों और प्रबन्धतंत्र के बीच औद्योगिक विवाद।

[संख्या एल०-29025/81/78-डी० 3 बी०]

आर० कुंजीथापदम, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th December, 1978

S.O. 3676.—Whereas an industrial dispute specified in the Schedule hereto annexed is pending before Shri K. Seetharama Rao, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Madras;

And, whereas, the services of the said Shri Seetharama Rao are no longer available;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and sub-section (1) of Section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri K. Selvaratnam shall be the Presiding Officer with headquarters at Madras to reconsider the entire matter afresh with reference to the aforesaid dispute in the light of the directions given by the Madras High Court in Writ Appeal No. 90 of 1976 and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Industrial dispute between the workmen and the Management of Messrs Dalmia Magnesite Corporation Salem vide this Ministry's Order No. 12(36)/70-LR-IV dated the 22nd January, 1971.

[No. L-29025/81/78-D. III. B]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

New Delhi, the 13th December, 1978

S.O. 3677.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal. Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Syndicate Bank and Shri A. Sripati Rao, Clerk, Chickpet Branch over the termination of his services, which was received by the Central Government on 28-11-78.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT BOMBAY

Reference No. 24 of 1977

Employers in relation to Syndicate Bank, Manipal

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the employers : Shri K. Rangaswamy, Personnel Officer.

For the workmen—Shri M. S. N. Rao, General Secretary, Syndicate Bank Staff Union.

INDUSTRY : Banking. STATE : Karnataka.

Bombay, the 9th November, 1978

AWARD

The Central Government in exercise of the powers conferred by Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, by Order dated 5th December, 1977, has referred the following dispute for adjudication by this Tribunal :—

SCHEDULE

"Whether the Management of Syndicate Bank was justified in terminating the services of Shri A. Sripati Rao, Clerk, Chickpet Branch ? If not, to what relief is the employee entitled ?"

After the receipt of the Reference, notices were issued to the parties for filing their written statements. Thereafter the matter was being adjourned from time to time at the request of the parties. However, the parties have filed a joint memorandum of settlement and prayed that an Award be made in terms of the settlement arrived at by them.

I have gone through the terms of settlement and find them fair and reasonable and make my Award in terms of the Settlement dated 4th November, 1978 (Schedule 'A' attached).

J. NARAIN, Presiding Officer

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT BOMBAY

I.D. No. CGIT 24 of 1977

Workmen of Syndicate Bank, (Head office : Manipal) REGD. POST

Represented by the Syndicate Bank

Staff Union, 5 Meeran Sahib Street

Mount Road

Madras—600002. PETITIONER.

V/s.

The Management of Syndicate Bank, Head Office, Manipal. RESPONDENT/OPPOSITE PARTY.

The parties to the above referred to dispute are filing herewith the Joint Memorandum of Settlement and request the Hon'ble Tribunal to take the same on record and pass necessary orders.

For the Petitioner-workmen
Sd./-
(M. S. N. RAO)
General Secretary,
Syndicate Bank Staff Union.

For the Management
Sd./-
(K. RANGASWAMY)
Personnel Manager,
Syndicate Bank.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT BOMBAY

I.D. No. CGIT 24 of 1977

Workmen of Syndicate Bank,
(Head Office : Manipal),
Represented by the Syndicate Bank Staff Union.
5 Meeran Sahib Street
Mount Road, Madras-600002 PETITIONER

V/s.

The Management of Syndicate Bank, Head Office, Manipal. RESPONDENT/ OPPOSITE PARTY

JOINT MEMORANDUM OF SETTLEMENT FILED BY THE PARTIES

May it please the Hon'ble Tribunal.

The petitioner, viz., the Syndicate Bank Staff Union, representing the petitioner-workmen and the Respondent viz., the Management of Syndicate Bank (Head Office, Manipal) beg to submit the following Joint Memorandum of Settlement as under and to state as follows :—

Whereas the parties to the dispute, viz., the Syndicate Bank Staff Union, representing the petitioner-workmen on the one side, and the Management of the Respondent Bank on the other, desired to settle the matter through mutual discussions and whereas as a result of such mutual discussions, it was agreed that the dispute be settled and treated as resolved on the under noted terms and conditions, and whereas the parties desire that the said terms of settlement be accepted by the Hon'ble Industrial Tribunal and an award passed in terms thereof, the parties have agreed to and accepted the following :—

TERMS OF SETTLEMENT

1. The Management having already reinstated Sri A. Sripathi Rao at the instance of the Petitioner considering his further request petition dated 15/7/1977 even prior to the Government's Order of reference for adjudication to the Hon'ble Central Government Industrial Tribunal, Bombay and passed orders of reinstatement vide their orders No. 14/APO/CMN/77 dated 26-7-1977, it is hereby agreed that parties to request the Hon'ble Tribunal to pass an award accordingly.

2. The period from 16-12-1975 to 3-8-1977 shall be treated as extraordinary leave without wages, subject to the proviso that such extraordinary leave shall be exclusive of any extra ordinary leave permissible in terms of the Bipartite Settlement in force from time to time.

3. The parties agree that the above terms are in full and final settlement of all issues involved in ID No : 24 of 1977 on the file of the Central Government Industrial Tribunal at Bombay and neither party shall have any claim over the other in respect of any matter or issue involved in the above dispute, save and to the extent of the terms and conditions of the Settlement set out above.

4. The parties pray that the Hon'ble Central Government Industrial Tribunal be pleased to accept this Joint Memorandum of settlement and be pleased to pass an award in terms thereof.

Dated at Manipal this the 4th day of November, 1978.

For the Petitioner-workmen
Sd./-
M. S. M. RAO
General Secretary,
Syndicate Bank Staff Union.

For the Management
Sd./-
(K. AJIT PRASAD RAI)
Personnel Manager,
Syndicate Bank

Witnesses :

Sd./-
(U. S. A. NAYAK)
State Secretary,
Syndicate Bank Staff Union.

Witnesses :

Sd./-
(K. RANGASWAMY)
Asstt. Personnel Manager,
Syndicate Bank.

J. NARAIN, Presiding Officer

[No. L-12012/70/77-D. IT-A]
S. K. MUKERJEE, Under Secy.

वित्त मन्त्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1978

सीमा-शुल्क

का. आ. 3678.—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 228/77-सी. शु., तारीख 26 अक्तूबर, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, मद (12) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(13) चांदी" ।

[अधिसूचना सं. 236/78-सी. शु./फा. सं. 481/49/77-सी. शु. 7]

एन. कृष्णमूर्ति, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi the 23rd December, 1978

CUSTOMS

S.O. 3678.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 228/77-Customs, dated 26th October, 1977, namely :—

In the said notification, after item (xii) the following item shall be inserted, namely :—

"(xiii) Silver."

[Notification No. 236/78-Customs/F. No. 481/49/77-Cus. VII]

N. KRISHNAMURTHY, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978